

(तिथि 18 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट))

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के वर्ष 2025-26 के बजट में बतौर वित्त मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग को 17 हजार 848 करोड़ रुपये से अधिक और उच्चतर शिक्षा विभाग को 3 हजार 874 करोड़ रुपये तथा आईटीआई विभाग को 574 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बजट में राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों की तर्ज पर हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके इलावा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों एवं अध्यापकों द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाये जाने की घोषणा की गई है। बजट में कहा गया है कि कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक लाख रुपये वार्षिक तक की छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। 3 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार में विश्वविद्यालयों के प्रांगणों में स्थित महाविद्यालयों में बीएससी कोर्सेस में पढ़ रही लड़कियों की ट्यूशन फीस माफ होगी। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा। कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को “सीखते हुए कमाएं” मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत चयनित विद्यार्थी को 6,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा, जिसके लिए 36 करोड़ के बजट का प्रस्ताव किया गया है। बजट में विश्व कौशल ओलंपिक में हरियाणा के पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये तक का नकद पुरस्कार देने का प्रस्ताव भी है। यदि वे स्वयं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहें, तो उन्हें सरकार द्वारा 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा रेवाड़ी स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में नए खेल उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाने की घोषणा भी की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा कल प्रस्तुत किए गए बजट पर विभिन्न वर्गों ने प्रतिक्रिया दी है। यहाँ सत्ता पक्ष ने इसे सभी वर्गों के हित का बजट बताया है वहीं विपक्ष ने इसकी आलोचना की है।

भिवानी के एक नागरिक सोमबीर शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना के लिए समर्पित मोबाइल ऐप जारी किया। यह सहज ज्ञान इंटरफ़ेस, सुगम डिज़ाइन और सरल नेविगेशन युक्त है जिसमें आधार फेस सत्यापन के ज़रिए आसानी से पंजीकरण किया जा सकता है। उम्मीदवारों को नए अपडेट से अवगत रखने के लिए इसमें रीयल टाइम अलर्ट सहित कई सुविधाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने रोज़गार, कौशल विकास और अवसरों को बढ़ावा देने की पांच योजनाओं के पैकेज प्रस्तुत करने में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम इंटरनशिप योजना में कक्षा में सीखने और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है जिससे युवाओं की रोज़गार क्षमता बढ़ेगी। इससे देश में कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलेगा जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। उन्होंने उद्योग जगत से इस योजना में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पीएमआईएस ऐप आरंभ होने से युवाओं के लिए इंटरनशिप अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना का लक्ष्य पांच वर्ष में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप अवसर प्रदान करना है।